UPSC LENS

दैनिक समाचार संक्षेप

संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा हेतु चयनित समसामयिक घटनाएँ

13 May 2026

7 विशेष विषय • GS-I • GS-II • GS-III

कार्यकारी सारांश | Executive Summary

आज के समाचार पत्रों से UPSC प्रासंगिक 7 विषयों का चयन किया गया है, जो राजव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, सामाजिक न्याय एवं विज्ञान व प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों को आवरित करते हैं।

क्र.सं.	विषय	एक पंक्ति सारांश	विषय श्रेणी	UPSC महत्व
1	**सबरीमाला पुनर्विचार: अनुच्छेद 25 और 26 पर सर्वोच्च न्यायालय की नौ-न्यायाधीश पीठ**	CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता में नौ-न्यायाधीश पीठ 2018 के सबरीमाला निर्णय की समीक्षा कर रही है – धार्मिक स्वतंत्रता बनाम सामाजिक सुधार का संवैधानिक प्रश्न।	राजव्यवस्था एवं शासन	**अत्यधिक महत्वपूर्ण**
2	**रुपया रिकॉर्ड निम्न स्तर पर; मुख्य आर्थिक सलाहकार ने व्यापक आर्थिक प्राथमिकताएँ रेखांकित कीं**	रुपया 95.75 प्रति डॉलर के सर्वकालिक न्यूनतम स्तर पर पहुँचा; CEA V. अनंत नागेश्वरन ने CII वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 में रुपये के अवमूल्यन को रोकना केंद्रीय व्यापक आर्थिक प्राथमिकता बताया।	अर्थव्यवस्था	**अत्यधिक महत्वपूर्ण**
3	**भारत-चीन-पाकिस्तान: ऑपरेशन सिंदूर और चीनी तकनीकी सहायता**	भारत के MEA ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीनी ऑन-साइट तकनीकी सहायता को उजागर किया; AVIC के एक अभियंता ने CCTV पर इसकी पुष्टि की।	अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं सुरक्षा	**अत्यधिक महत्वपूर्ण**
4	**NSAP वृद्धावस्था पेंशन का वास्तविक क्षरण: प्रभाव आकलन रिपोर्ट**	ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट: NSAP पेंशन 2012 से अपरिवर्तित; 91% मुद्रास्फीति से वास्तविक मूल्य में 45% की गिरावट; CPI-सूचीबद्ध राष्ट्रीय न्यूनतम पेंशन की सिफारिश।	सामाजिक न्याय एवं कल्याण	महत्वपूर्ण
5	**राज्यों के पूँजीगत व्यय ऋण नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने से जोड़े गए (SASCI योजना)**	केंद्र ने SASCI के अंतर्गत ब्याज-मुक्त पूँजीगत ऋण को नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने से जोड़ा; बजट 2026-27 में 2 लाख करोड़ रुपये के 50-वर्षीय ऋण का प्रावधान।	राजकोषीय संघवाद एवं ऊर्जा नीति	**अत्यधिक महत्वपूर्ण**
6	**भारत-UAE CEPA और स्वर्ण आयात की चुनौती**	FY26 में स्वर्ण आयात 25% बढ़कर $71.97 बिलियन; भारत-UAE CEPA	अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं अर्थव्यवस्था	महत्वपूर्ण

क्र.सं.	विषय	एक पंक्ति सारांश	विषय श्रेणी	UPSC महत्व
		की वजह से अनायास बुलियन आयात प्रोत्साहित होने से CAD पर दबाव बढ़ा।		
7	**PCOS का नाम बदलकर PMOS: The Lancet में प्रकाशित**	14 वर्षों के वैश्विक सहयोग के बाद PCOS का नाम बदलकर 'पॉली-एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम' (PMOS) किया गया; The Lancet में प्रकाशित; वैश्विक स्तर पर 17 करोड़ से अधिक महिलाएँ प्रभावित।	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी / स्वास्थ्य	महत्वपूर्ण

विषयवार विस्तृत विश्लेषण | Detailed Analysis

1. सबरीमाला पुनर्विचार: अनुच्छेद 25 और 26 पर सर्वोच्च न्यायालय की नौ-न्यायाधीश पीठ

■ राजव्यवस्था एवं शासन • UPSC महत्व: अत्यधिक महत्वपूर्ण

◆ संक्षिप्त परिचय

CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय की नौ-न्यायाधीश पीठ उन याचिकाओं की सुनवाई कर रही है जो 2018 के सबरीमाला निर्णय की समीक्षा की माँग करती हैं। उस निर्णय में महिलाओं के प्रवेश पर आयु-आधारित प्रतिबंध को समाप्त किया गया था। पीठ अनुच्छेद 25 (धर्म की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 26 (धार्मिक संप्रदायों के अधिकार) के बीच अंतर्संबंध तथा अनुच्छेद 25(2)(b) के अंतर्गत राज्य-नेतृत्व वाले सामाजिक सुधार की सीमाओं की जाँच कर रही है।

★ UPSC के लिए महत्व

- यह मामला सीधे अनुच्छेद 25 और 26 – जो GS-II के मुख्य विषय हैं – से जुड़ा है।
- सामाजिक सुधार और धार्मिक स्वायत्तता के बीच की सीमा पर मूलभूत प्रश्न उठाता है।
- नौ-न्यायाधीश पीठ की सुनवाई संवैधानिक महत्व का संकेत है; अंतिम निर्णय एक ऐतिहासिक मिसाल होगा।

संबंधित स्थैतिक विषय

- संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 14, 15
- अनिवार्य धार्मिक आचरण की अवधारणा
- धर्म के अधिकार बनाम समानता के अधिकार की न्यायशास्त्र परंपरा
- पूर्व निर्णय: सबरीमाला 2018, शिरूर मठ प्रकरण, दरगाह समिति प्रकरण

प्रारंभिक परीक्षा फोकस

- अनुच्छेद 25(1) – अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र आचरण का अधिकार
- अनुच्छेद 25(2)(b) – हिंदू संस्थाओं के संबंध में सामाजिक सुधार हेतु राज्य की विधायी शक्ति
- अनुच्छेद 26 – धार्मिक संप्रदायों को अपने मामले स्वयं प्रबंधित करने का अधिकार
- लोक नैतिकता और संवैधानिक नैतिकता के बीच अंतर

✍ मुख्य परीक्षा फोकस

- GS-II: क्या राज्य द्वारा अनिवार्य सामाजिक सुधार संवैधानिक रूप से संरक्षित धार्मिक अधिकारों को अधिरोहित कर सकता है? सबरीमाला के संदर्भ में विवेचना करें।
- GS-II: अनुच्छेद 25 और 26 के बीच तनाव और धार्मिक सुधार में न्यायपालिका की भूमिका का परीक्षण करें।

🔑 महत्वपूर्ण शब्द

अनुच्छेद 25 • अनुच्छेद 26 • सबरीमाला • सामाजिक सुधार • धार्मिक संप्रदाय • अनिवार्य धार्मिक आचरण • CJI सूर्यकांत • नौ-न्यायाधीश पीठ • संवैधानिक नैतिकता

2. रुपया रिकॉर्ड निम्न स्तर पर; मुख्य आर्थिक सलाहकार ने व्यापक आर्थिक प्राथमिकताएँ रेखांकित कीं

■ **अर्थव्यवस्था** • UPSC महत्व: **अत्यधिक महत्वपूर्ण**

◆ संक्षिप्त परिचय

भारतीय रुपया 95.75 प्रति डॉलर के सर्वकालिक न्यूनतम स्तर पर पहुँचने के बाद 95.63 पर बंद हुआ। यह गिरावट पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़े वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में संरचनात्मक बदलावों के कारण हुई। मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) V. अनंत नागेश्वरन ने CII वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 में बोलते हुए रुपये के आगे अवमूल्यन को रोकना चालू वित्त वर्ष की केंद्रीय व्यापक आर्थिक प्राथमिकता के रूप में रेखांकित किया।

★ UPSC के लिए महत्व

- विनिमय दर प्रबंधन और चालू खाता घाटे से इसका संबंध GS-III के नियमित विषय हैं।
- मुद्रा स्थिरीकरण में CEA की भूमिका और तंत्र आर्थिक शासन से संबंधित हैं।
- बाहरी आघात के रूप में पश्चिम एशिया संघर्ष का भारत की व्यापक आर्थिक स्थिरता पर प्रभाव विश्लेषणात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

संबंधित स्थैतिक विषय

- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA)
- विनिमय दर प्रबंधन में RBI की भूमिका
- चालू खाता घाटा (CAD) और भुगतान संतुलन

- कच्चे तेल की कीमतों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

प्रारंभिक परीक्षा फोकस

- भारत की आर्थिक नीति-निर्माण में मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) की भूमिका
- विनिमय दर निर्धारित करने वाले कारक – ब्याज दर अंतर, मुद्रास्फीति, CAD
- CII (भारतीय उद्योग परिसंघ) – प्रकृति एवं भूमिका

मुख्य परीक्षा फोकस

- GS-III: बाहरी आघातों के प्रति भारतीय रुपये की संरचनात्मक कमजोरियों का परीक्षण करें। सरकार और RBI के पास कौन से नीतिगत उपकरण उपलब्ध हैं?
- GS-III: भारत की व्यापक आर्थिक स्थिरता पर पश्चिम एशिया संघर्ष के प्रभाव का विश्लेषण करें।

महत्वपूर्ण शब्द

रुपये का अवमूल्यन • CEA • V. अनंत नागेश्वरन • चालू खाता घाटा • CII • व्यापक आर्थिक स्थिरता • पश्चिम एशिया संघर्ष • विनिमय दर

3. भारत-चीन-पाकिस्तान: ऑपरेशन सिंदूर और चीनी तकनीकी सहायता

अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं सुरक्षा • UPSC महत्व: **अत्यधिक महत्वपूर्ण**

संक्षिप्त परिचय

भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने पाहलगाम आतंकी हमले के बाद आरंभ किए गए भारतीय आतंकवाद-रोधी सैन्य अभियान 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान पाकिस्तान को चीन द्वारा ऑन-साइट तकनीकी सहायता प्रदान करने का तथ्य उजागर किया। चीन के सरकारी प्रसारणकर्ता CCTV ने Aviation Industry Corporation of China (AVIC) के एक अभियंता का साक्षात्कार प्रसारित किया, जिसने ऐसी सहायता की पुष्टि की। भारत ने कहा कि आतंकी अवसंरचना का समर्थन करने वाले देशों को इसके प्रतिष्ठात्मक परिणामों पर विचार करना चाहिए।

UPSC के लिए महत्व

- भारत-चीन-पाकिस्तान रणनीतिक त्रिकोण GS-II और GS-III (रक्षा) का एक बारहमासी विषय है।
- क्षेत्रीय संघर्षों में चीनी रक्षा हार्डवेयर (J-10CE जेट) और दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकी की भूमिका को उजागर करता है।

- MEA प्रवक्ता के माध्यम से भारत का राजनयिक संकेत विदेश नीति के उपकरणों को समझने के लिए प्रासंगिक है।

संबंधित स्थैतिक विषय

- भारत-चीन संबंध: सीमा विवाद, रणनीतिक प्रतिस्पर्धा, वास्तविक नियंत्रण रेखा
- भारत-पाकिस्तान संबंध: सीमापार आतंकवाद, सिंधु जल संधि
- Aviation Industry Corporation of China (AVIC) और चीनी रक्षा निर्यात
- भारत का आतंकवाद-रोधी सिद्धांत

प्रारंभिक परीक्षा फोकस

- J-10CE लड़ाकू विमान – मूल देश (चीन), संचालक (पाकिस्तान)
- AVIC – Aviation Industry Corporation of China
- ऑपरेशन सिंदूर – संदर्भ और आतंकवाद-रोधी अभियान के रूप में प्रकृति
- भारतीय विदेश नीति संचार में MEA प्रवक्ता की भूमिका

मुख्य परीक्षा फोकस

- GS-II: पाकिस्तान को चीनी सैन्य-तकनीकी सहायता भारत के सुरक्षा गणित को कैसे प्रभावित करती है? भारत के राजनयिक विकल्पों का मूल्यांकन करें।
- GS-III: दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय स्थिरता के लिए पाकिस्तान को चीनी रक्षा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के निहितार्थों का आकलन करें।

महत्वपूर्ण शब्द

ऑपरेशन सिंदूर • चीन-पाकिस्तान • AVIC • J-10CE • MEA • आतंकवाद-रोधी • भारत-चीन संबंध • रक्षा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण • पाहलगाम हमला

4. NSAP वृद्धावस्था पेंशन का वास्तविक क्षरण: प्रभाव आकलन रिपोर्ट

■ **सामाजिक न्याय एवं कल्याण** • UPSC महत्व: **महत्वपूर्ण**

संक्षिप्त परिचय

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कमीशन किए गए एक मूल्यांकन में पाया गया कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन में केंद्र का योगदान 2012 से 200-500 रुपये प्रति लाभार्थी प्रति माह पर अपरिवर्तित है। 2012 से 2024 के बीच लगभग 91% संचयी मुद्रास्फीति के कारण वास्तविक मूल्य में लगभग 45% की कमी आई है। अध्ययन में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) से सूचीबद्ध राष्ट्रीय न्यूनतम पेंशन (NFP) की शुरुआत की सिफारिश की गई है।

★ UPSC के लिए महत्व

- NSAP ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख केंद्र प्रायोजित योजना है – प्रारंभिक परीक्षा में बार-बार परीक्षित।
- अध्ययन सामाजिक सुरक्षा पर्याप्तता, मुद्रास्फीति सूचीकरण और कल्याणकारी राज्य दायित्वों के महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है।
- NFP की सिफारिश राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन अवधारणा से मेल खाती है – तुलनात्मक विश्लेषण हेतु उपयोगी।

संबंधित स्थैतिक विषय

- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) – 1995 में शुरू, पाँच उप-योजनाएँ
- IGNOAPS, IGNWPS, IGNDPS, NFBS, अन्नपूर्णा योजना
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) और मुद्रास्फीति मापन
- राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम

प्रारंभिक परीक्षा फोकस

- NSAP – 1995 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत शुरू
- NSAP के पाँच घटक: IGNOAPS, IGNWPS, IGNDPS, NFBS, अन्नपूर्णा
- वर्तमान पेंशन राशि: 200 रुपये (60-79 वर्ष), 500 रुपये (80+ वर्ष)
- पेंशन राशि 2012 में अंतिम बार संशोधित की गई थी

मुख्य परीक्षा फोकस

- GS-II: भारत के सामाजिक पेंशन कार्यक्रमों की पर्याप्तता का समालोचनात्मक परीक्षण करें। क्या कल्याण अंतरण को मुद्रास्फीति से सूचीबद्ध किया जाना चाहिए?
- GS-III: CPI से जुड़े राष्ट्रीय न्यूनतम पेंशन की शुरुआत के राजकोषीय और सामाजिक निहितार्थों का विश्लेषण करें।

महत्वपूर्ण शब्द

NSAP • IGNOAPS • वृद्धावस्था पेंशन • राष्ट्रीय न्यूनतम पेंशन • CPI सूचीकरण • सामाजिक सुरक्षा • ग्रामीण विकास मंत्रालय • कल्याण क्षरण

5. राज्यों के पूँजीगत व्यय ऋण नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने से जोड़े गए (SASCI योजना)

■ राजकोषीय संघवाद एवं ऊर्जा नीति • UPSC महत्व: अत्यधिक महत्वपूर्ण

◆ संक्षिप्त परिचय

केंद्र सरकार ने राज्यों हेतु पूँजीगत निवेश विशेष सहायता (SASCI) योजना के अंतर्गत ब्याज-मुक्त पूँजीगत व्यय ऋण की पात्रता को नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने से जोड़ने की नीति को मंजूरी दी है। केंद्रीय बजट 2026-27 में SASCI के तहत 50-वर्षीय ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में 2 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिनमें 75,000 करोड़ रुपये अनुबंध-मुक्त हैं और शेष सुधार प्रदर्शन से जुड़े हैं। नवीकरणीय ऊर्जा अपनाना अब अनुबद्ध घटक की शर्त है।

★ UPSC के लिए महत्व

- SASCI एक महत्वपूर्ण राजकोषीय संघवाद उपकरण है – GS-II (संघवाद) और GS-III (अर्थव्यवस्था, ऊर्जा) के लिए प्रासंगिक।
- स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को राजकोषीय ढाँचे में एकीकृत करना भारत के ऊर्जा परिवर्तन के लिए एक प्रमुख नीतिगत नवाचार है।
- FRBM अधिनियम, राज्य उधारी सीमाओं और केंद्रीय पूँजीगत व्यय समर्थन का अंतर्संबंध एक नियमित परीक्षा क्षेत्र है।

संबंधित स्थैतिक विषय

- राज्यों हेतु पूँजीगत निवेश विशेष सहायता (SASCI)
- राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम – राज्यों के लिए 3% GSDP उधारी सीमा
- केंद्र-राज्य राजकोषीय संबंध और वित्त आयोग हस्तांतरण
- भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य और जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना

प्रारंभिक परीक्षा फोकस

- SASCI – 50-वर्षीय ब्याज-मुक्त ऋण, बजट 2026-27 में 2 लाख करोड़ रुपये
- अनुबंध-मुक्त घटक: 75,000 करोड़ रुपये; शेष राज्य सुधार प्रदर्शन से जुड़े
- FRBM अधिनियम – राज्यों की शुद्ध उधारी सीमा GSDP के 3%
- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय – मंत्री प्रल्हाद जोशी

✍ मुख्य परीक्षा फोकस

- GS-III: राजकोषीय प्रोत्साहनों का उपयोग भारत के ऊर्जा परिवर्तन को कैसे गति दे सकता है? SASCI-नवीकरणीय ऊर्जा संबंध का परीक्षण करें।
- GS-II: सहकारी संघवाद के उपकरण के रूप में केंद्र-राज्य पूँजी हस्तांतरण में शर्तों के उपयोग का मूल्यांकन करें।

🔑 महत्वपूर्ण शब्द

SASCI • पूँजीगत ऋण • नवीकरणीय ऊर्जा • राजकोषीय संघवाद • FRBM अधिनियम • ब्याज-मुक्त ऋण • स्वच्छ ऊर्जा • CII शिखर सम्मेलन 2026 • प्रल्हाद जोशी

6. भारत-UAE CEPA और स्वर्ण आयात की चुनौती

■ **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं अर्थव्यवस्था** • UPSC महत्व: **महत्वपूर्ण**

◆ संक्षिप्त परिचय

भारत का स्वर्ण आयात FY26 में मूल्य में लगभग 25% बढ़कर $71.97 बिलियन हो गया, हालाँकि आयात मात्रा गिरकर 721 टन हो गई, जो सोने की कीमतों में तेज वृद्धि को दर्शाता है। फरवरी 2022 में हस्ताक्षरित भारत-UAE व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) अनायास ही डोरे के बजाय बुलियन आयात को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि इसने तैयार बुलियन के लिए अधिक अनुकूल शुल्क ढाँचा बनाया है, जिससे भारत का चालू खाता घाटा बढ़ा है। भारत में केवल एक LBMA-मान्यता प्राप्त रिफाइनरी है।

★ UPSC के लिए महत्व

- भारत-UAE CEPA एक महत्वपूर्ण व्यापार समझौता है – GS-II (द्विपक्षीय संबंध) और GS-III (व्यापार) के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रासंगिक।
- CAD के चालक के रूप में स्वर्ण आयात UPSC GS-III का एक मानक व्यापक अर्थशास्त्र विषय है।
- डोरे बनाम बुलियन का अंतर और घरेलू मूल्य संवर्धन का पहलू सूक्ष्म विश्लेषणात्मक सामग्री प्रदान करता है।

संबंधित स्थैतिक विषय

- व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) – परिभाषा, भारत के CEPA
- चालू खाता घाटा – घटक और प्रबंधन

- लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन (LBMA) और स्वर्ण शोधन मानक
- गोल्ड डोरे – परिभाषा (खदान स्थलों से अर्ध-शुद्ध स्वर्ण-चाँदी मिश्रधातु)

प्रारंभिक परीक्षा फोकस

- भारत-UAE CEPA फरवरी 2022 में हस्ताक्षरित
- गोल्ड डोरे – खदान स्थलों पर निर्मित सोने और चाँदी की अर्ध-शुद्ध मिश्रधातु
- LBMA – लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन; भारत में केवल एक LBMA-मान्यता प्राप्त रिफाइनरी
- FY26 में स्वर्ण आयात मूल्य: $71.97 बिलियन (FY25 से 25% वृद्धि)

मुख्य परीक्षा फोकस

- GS-III: भारत-UAE CEPA और स्वर्ण आयात के संदर्भ में परीक्षण करें कि व्यापार समझौते अनायास ही व्यापक आर्थिक परिणाम कैसे उत्पन्न कर सकते हैं।
- GS-III: भारत की स्वर्ण आयात निर्भरता कम करने और घरेलू शोधन क्षमता को मजबूत करने के लिए कौन से संरचनात्मक सुधार आवश्यक हैं?

महत्वपूर्ण शब्द

भारत-UAE CEPA • स्वर्ण आयात • चालू खाता घाटा • गोल्ड डोरे • LBMA • बुलियन • व्यापार घाटा • शोधन क्षमता • FY26

7. PCOS का नाम बदलकर PMOS: The Lancet में प्रकाशित

■ **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी / स्वास्थ्य** • UPSC महत्व: **महत्वपूर्ण**

संक्षिप्त परिचय

14 वर्षों के वैश्विक सहयोग के बाद, जिसमें चिकित्सक, शोधकर्ता, रोगी समूह और व्यावसायिक समितियाँ शामिल थीं, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (PCOS) का नाम बदलकर 'पॉली-एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम' (PMOS) कर दिया गया है। The Lancet में प्रकाशित यह परिवर्तन केवल डिम्बग्रंथि पुटकों से परे अंतःस्रावी, चयापचय और प्रजनन प्रणालियों पर इस स्थिति के व्यापक प्रभाव को दर्शाता है। वैश्विक स्तर पर लगभग 17 करोड़ से अधिक महिलाएँ इससे प्रभावित हैं।

UPSC के लिए महत्व

- एक प्रमुख पत्रिका (The Lancet) में प्रकाशित एक प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य स्थिति का नामकरण परिवर्तन GS-III (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य) के लिए प्रासंगिक है।

- वैश्विक स्वास्थ्य सहमति-निर्माण में भारत की भूमिका उल्लेखनीय है।
- चयापचय आयाम भारत पर चयापचय सिंड्रोम, इंसुलिन प्रतिरोध और मधुमेह के उच्च बोझ से जुड़ता है।

संबंधित स्थैतिक विषय

- अंतःस्रावी तंत्र – हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, डिम्बग्रंथि अक्ष
- चयापचय सिंड्रोम – इंसुलिन प्रतिरोध, मोटापा, मधुमेह संबंध
- The Lancet – सहकर्मी-समीक्षित चिकित्सा पत्रिका
- वैश्विक स्वास्थ्य शासन और रोग वर्गीकरण में WHO की भूमिका

प्रारंभिक परीक्षा फोकस

- नया नाम: पॉली-एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम (PMOS); पुराना नाम: PCOS
- The Lancet में प्रकाशित
- वैश्विक स्तर पर लगभग 8 में से 1 महिला प्रभावित; 17 करोड़ से अधिक महिलाएँ
- भारत में व्यापकता: 16-19% (लेख के अनुसार)
- Monash Centre for Health Research and Implementation – नामकरण प्रक्रिया में शामिल

मुख्य परीक्षा फोकस

- GS-III: सटीक रोग नामकरण से सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणाम कैसे सुधरते हैं? PCOS से PMOS नामकरण के संदर्भ में विवेचना करें।
- GS-II: भारत में महिलाओं में चयापचय-अंतःस्रावी विकारों के निदान और उपचार में चुनौतियों का परीक्षण करें।

महत्वपूर्ण शब्द

PMOS • PCOS • पॉली-एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम • The Lancet • अंतःस्रावी विकार • चयापचय सिंड्रोम • महिला स्वास्थ्य • भारतीय सहायक प्रजनन समिति